मुख्यमंत्री का भीलवाड़ा-उदयपुर में रोड शो, मदन राठौड़ अजमेर, नागौर जाएंगे

भाजपा ने नगर निकाय चुनावों के प्रचार में वरिष्ठ नेताओं को उतारा

■ **भाजपा की रणनीति है कि पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतर कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करें।**

जयपुर, 4 सितम्बर। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव प्रचार अब पूरी तरह जोर पकड़ चुका है। भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारते हुए, शनिवार, 5 सितंबर के लिये व्यापक प्रचार अभियान की रणनीति बनाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अजमेर और नागौर के प्रवास पर रहेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा और उदयपुर में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाएंगे। मुख्यमंत्री दोनों शहरों में रोड शो के साथ संगठनात्मक बैठकों में भी चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार को अजमेर और नागौर में चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होंगे। उनके प्रवास के दौरान, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क और चुनावी गतिविधियों को गति देने के साथ ही, स्थानीय संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया जाएगा।

भाजपा की कोशिश है कि प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करें। टिकट वितरण के बाद जहां कहीं नाराजगी या बगावत की स्थिति बनी है, वहां भी नेताओं के प्रवास को संगठनात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार सुबह जयपुर से रवाना होकर करीब 11.50 बजे भीलवाड़ा पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे से उनका रोड शो शुरू होगा। रोड शो दूधाधारी गोपाल मंदिर परिसर से शुरू होकर निर्धारित मार्ग पर चलेगा।

इसके बाद, दोपहर 1 से 2 बजे तक मुख्यमंत्री भाजपा जिला कार्यालय, भीलवाड़ा में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। यहां स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों, संगठन की स्थिति और चुनावी रणनीति को लेकर नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा।

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। करीब 2.40 बजे उदयपुर पहुंचने के बाद शाम चार बजे उनका रोड शो प्रस्तावित है।

उदयपुर में मुख्यमंत्री का रोड शो शाम 4 बजे सूरजपोल चौराहे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा स्थल से शुरू होगा। करीब एक घंटे तक चलने वाले रोड शो में मुख्यमंत्री पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे।

रोड शो के बाद शाम 5 से 6 बजे तक मुख्यमंत्री संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे।

एयर इंडिया का फुकेत -दिल्ली उड़ान का मुख्य पायलट बर्खास्त

मुंबई, 04 सितंबर। टाटा की अगुवाई वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने शुक्रवार को फुकेत-दिल्ली फ़्लाइट के पायलट-इन-कमांड की सेवाएं समाप्त कर दीं है, जो ड्रग्स के इस्तेमाल के टैस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। एयर इंडिया ने आज एक बयान में बताया कि जांच में मादक पदार्थ सेवन की पुष्टि होने पर फुकेत-दिल्ली उड़ान के मुख्य पायलट की सेवा समाप्त कर दी गई। विमानन कंपनी की ओर से यह घोषणा फुकेत फ़्लाइट की घटना की जांच करने वाली एजेंसी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की शुरुआती रिपोर्ट आने के कुछ घंटों बाद की गई है। एएआईबी की इस रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट द्वारा मादक पदार्थ का सेवन एक गंभीर चिंता का विषय है और उसने विमान नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से उचित कार्रवाई करने को कहा था।

बीएल संतोष ने दिन भर की बैठकों में चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया

उन्होंने कहा, कमज़ोर नज़र आ रहे प्रत्याशी के साथ खड़ा होकर संगठन उसे मजबूत बनाएं

■ **राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, चुनावी प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया।**

जयपुर, 4 सितम्बर। राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने अब चुनावी अभियान को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिनभर चली विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया और नेताओं-कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बैठक में, पार्टी प्रत्याशियों की स्थिति, बूथ प्रबंधन, स्थानीय समीकरण, वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता, बागियों और नाराज कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय के साथ-साथ, मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री एवं निकाय चुनाव प्रभारी हरीश द्विवेदी, प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी गजेन्द्र पटेल, रोहन गुप्ता और संगीता यादव तथा संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में, कुछ वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों की स्थिति को लेकर फीडबैक सामने आया। ऐसे वार्डों पर भी चर्चा हुई, जहां मुकाबला कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर ऐसे स्थानों पर चुनाव के बाद बोर्ड गठन के संभावित समीकरणों को देखते हुए निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क की चर्चा भी उठी।

लेकिन संतोष ने चुनाव के दौरान इस तरह के विकल्प तलाशने के बजाय, अधिकृत प्रत्याशी को जिताने पर पूरा जोर देने का संदेश दिया। उनका स्पष्ट संकेत था कि प्रत्याशी कमजोर नजर आ रहा है तो संगठन को उसके साथ खड़ा होकर उसे मजबूत करना चाहिए।

यह संदेश टिकट वितरण के बाद कुछ स्थानों पर सामने आई नाराजगी और बगावत के बीच भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठन की कोशिश है कि स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में पूरी ताकत लगाई जाए।

बैठक में वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की चुनावी सक्रियता पर भी चर्चा हुई। एक वरिष्ठ नेता की ओर से कुछ सांसदों की अपेक्षाकृत कम सक्रियता का मुद्दा उठाया गया। इसके बाद संतोष ने स्पष्ट किया कि निकाय चुनाव केवल वार्ड प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, बल्कि संगठन के हर स्तर की सक्रियता इसमें मायने रखती है।

मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक में संतोष ने भाजपा के खिलाफ चल रहे नरेटिव को लेकर भी फीडबैक लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाए।

बैठक में संगठनात्मक गोपनीयता का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। संतोष ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कई बार पार्टी की आंतरिक बैठकों की जानकारी बैठक समाप्त होने से पहले ही बाहर और मीडिया तक पहुंच जाती है। उन्होंने ऐसे लोगों को लेकर सख्त संदेश दिया, जो संगठनात्मक बैठकों की अंदरूनी चर्चा सार्वजनिक करने या केवल मीडिया में खबरों में बने रहने के लिए सक्रिय रहते हैं।

अमेरिका की सहायता के लिये होर्मुज़ में सेना तैनात करेगा द.कोरिया

द.कोरिया होर्मुज़ से सुरक्षित समुद्री रास्ता सुनिश्चित करने के लिये सैन्य योगदान देने को तैयार है

■ **क्यूंगनाम युनिवर्सिटी के विज़िटिंग रिसर्च फैलो का कहना है कि सियोल होर्मुज़ में संभावित तैनाती को वॉशिंगटन के साथ व्यापार व गठबंधन से जुड़े अन्य मुद्दे हासिल करने के एक तरीके के रुप में देख सकता है।**

सियोल (दक्षिण कोरिया), 04 सितंबर। दक्षिण कोरिया होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में अमेरिका की मदद करने के लिए वहां सैन्य कर्मियों की तैनाती पर विचार कर रहा है।

"द कोरिया हेराल्ड" ने शुक्रवार को राष्ट्रपति कार्यालय चेओंग वा डे के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट में इस अधिकारी की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। इस अधिकारी ने कहा कि यह कोरियाई प्रायद्वीप पर रक्षा तैयारियों की स्थिति और घरेलू कानूनी जरूरतों के आधार पर तय किया जाएगा। हालांकि, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

यह बयान स्थानीय प्रसारक जेटीबीसी की गुरुवार की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया कि सरकार होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सैनिकों की तैनाती पर विचार कर रही है और नेशनल असेंबली में तैनाती की मंजूरी का प्रस्ताव पेश करने में अधिक समय नहीं लगेगा।

इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति भवन के अधिकारी ने कहा कि सरकार ने अभी किसी खास कार्रवाई का फैसला नहीं किया है। उन्होंने सियोल के इस रुख को दोहराया कि वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित समुद्री रास्ते सुनिश्चित करने में ठोस और सैन्य योगदान देगा।

अधिकारी ने कहा, "सियोल की सेना लड़ाई में भी अमेरिका का साथ दे सकती है।" इस अधिकारी ने कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में दक्षिण कोरिया के किसी भी "ठोस योगदान" के लिए सबसे पहले कोरियाई प्रायद्वीप पर देश की सैन्य तैयारी के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा।

क्यूंगनाम यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर फार ईस्टर्न स्टडीज में विजिटिंग रिसर्च फेलो डू जिन-हो ने सुझाव दिया कि सियोल होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित तैनाती को वाशिंगटन के साथ व्यापार और गठबंधन से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर बढ़त हासिल करने के एक तरीके के रूप में देख सकता है।

दुनिया भारत व अमेरिका के मजबूत रिश्तों से जलती है- राजदूत गोर

नई दिल्ली, 04 सितंबर। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दोनों देशों की गहरी होती साझेदारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य देश भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों से जलते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप जिन वैश्विक नेताओं से मिलना चाहते हैं, उस सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी टॉप पर हैं। इंडिया टुडे को दिए एक विशेष साक्षात्कार में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने रक्षा, व्यापार, कूटनीति और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों के बढ़ते दायरे पर विस्तार से बात की है।

■ **अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, ट्रंप 2020 की भारत यात्रा को बहुत गर्मजोशी से याद करते हैं**

सर्जियो गोर का कहना है कि फ्लोरिडा में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप जिन नेताओं से मिलना चाहते हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनकी पहली पसंद होंगे। राजदूत ने गोर ने अगले साल डॉनल्ड ट्रंप के भारत दौरे की संभावनाओं के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा, जब भी मेरी उनसे (ट्रंप से) बात होती है, वे अपनी 2020 की भारत यात्रा, यहां के शानदार लोगों और अपने खास दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को बेहद गर्मजोशी से याद करते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शुक्रवार को पूंछरी का लौंठा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके साथ ही, उन्होंने मुखारविंद मन्दिर में श्री गिरिराज जी का अभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की।

राहुल गांधी के प्र.मंत्री बनने में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ **अगर, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलगांना आदि राज्यों में कांग्रेस का मजबूत प्रदर्शन रहता है तो राहुल प्र.मंत्री की कुर्सी के नज़दीक पहुँच सकेंगे।**

और टीवीके (तमिलगा वेट्री कझगम) नेता विजय ने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता ताराहाई कथबर्ट ने मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि विजय और राहुल एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

लेकिन राजनीति शायद ही कभी पब्लिक को भरोसा दिलाने जितनी आसान होती है।

कुछ दिन पहले ही, विजय को पीएम बनाने के अभियान की खबरों के कारण कांग्रेस- टीवीके गठबंधन में काफी तनाव पैदा हो गया था। कांग्रेस के एक मंत्री ने यह धमकी तक दे दी थी कि अगर टीवीके 2029 के लिए राहुल गांधी का समर्थन करने से इनकार करती है, तो वे इस्तीफा दे देंगे।

यही बात राहुल गांधी की बुनियादी समस्या को उजागर करती है - भले ही कोई सहयोगी उनका समर्थन करे, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि वह समर्थन बिना किसी शर्त के हो।

इंडिया गठबंधन कभी भी एक पारंपरिक राजनीतिक पार्टी के तौर पर नहीं बनाया गया था, जिसका एक नेता, एक विचारधारा और एक कमान व्यवस्था (कमांड स्ट्रक्चर) हो। यह उन पार्टियों का चुनावी गठबंधन था, जिनकी क्षेत्रीय रुचियां और महत्वाकांक्षाएं एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। इसी वजह से शीर्ष पद के लिए राहुल गांधी का दावा विशेष रूप से मुश्किल हो जाता है।

ममता बनर्जी ने यह दिखा दिया था कि तृणमूल कांग्रेस की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं और ज़रूरी नहीं कि वह कांग्रेस को विपक्ष का निर्विवाद नेता माने। इसी तरह, अरविंद केजरीवाल की "आप" ने भी कांग्रेस से अलग अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश की थी।

वहीं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ताकतवर खिलाड़ी के तौर पर उभरी है और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व कौन करे, इसे लेकर उसका अपना गणित है।

राहुल गांधी के सामने यही मुख्य विरोधाभास है - कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की तरह काम करे, जबकि कई क्षेत्रीय पार्टियां इस गठबंधन को मुख्य रूप से भाजपा को हराने के एक ज़रिए के तौर पर देखती हैं- न कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए।

यह फ़र्क 2029 में निर्णायक साबित हो सकता है।

कांग्रेस का अपने नेता के प्रति लगातार लगाव पार्टी को राहुल से उम्मीद नहीं खोने देता और पार्टी 2014 के बाद से उनमें आए सकारात्मक बदलावों की ओर इशारा करती है। पार्टी का मानना है कि उनका राजनीतिक संवाद बेहतर हुआ है, संसद में उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और 'भारत जोड़ो यात्रा' ने उन्हें एक ऐसी छवि प्रदान की है, जो उनके विरोधियों द्वारा बनाई गई 'अनिच्छुक राजनेता' की छवि से बिल्कुल अलग है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव ने भी कांग्रेस का मनोबल बढ़ाया। पार्टी ने 2019 के अपने नतीजों में काफ़ी सुधार किया, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर उभरे हैं। लेकिन मज़बूत कांग्रेस का मतलब अपने आप ही यह नहीं हो जाता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए आम सहमति वाले उम्मीदवार बन जाएंगे।

इसके लिए, कांग्रेस को एक ज़्यादा मुश्किल सवाल का जवाब देना होगा - वह वास्तव में अपने दम पर कितनी सीटें जीत सकती है, और क्षेत्रीय सहयोगियों पर कितनी निर्भर रहेगी?

इस सवाल का जवाब ही राहुल गांधी की मोल-भाव करने की क्षमता तय करेगा।

अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो राहुल का दावा काफ़ी मज़बूत हो जाएगा। लेकिन अगर अहम राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हावी रहती हैं, तो प्रधानमंत्री पद का सवाल एक बार फिर चुनाव के बाद बातचीत का मुद्दा बन सकता है।

यहीं पर सी एम विजय अहम हो जाते हैं।

नया नीतीश कुमार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का एक वर्ग, दोनों ही यह पूछने लगे हैं कि उस राजनीतिक जगह का क्या होगा, जिस पर वे इतने लंबे समय तक काबिज़ रहे। कई लोग दावा करेंगे। कुशवाहा ने औपचारिक रूप से खुद को नीतीश का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि एक बड़ा वर्ग चाहेगा कि वे यह जिम्मेदारी संभालें।

उत्तराधिकार का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राजनेता के तौर पर नीतीश की जगह कौन लेगा। सवाल यह है कि उनके पीछे छोड़ी गई राजनीतिक परंपरा का वाहक कौन होगा, खासकर समाजवादी, पिछड़ी जाति वाली वह जगह, जिसने कभी नीतीश को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और भाजपा, दोनों से अलग खड़ा होने में मदद की थी।

यहीं पर कुशवाहा की भूमिका अहम हो जाती है। वे आज बिहार में नीतीश की राजनीतिक शैली के संभावित उत्तराधिकारी के शायद सबसे करीब हैं। नीतीश की तरह, वे भी कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण द्वारा गढ़ी गई समाजवादी परंपरा से आते हैं; नीतीश की तरह, वे पिछड़ी जाति के उस सामाजिक गठबंधन के महत्व को समझते हैं, जिसने लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) समीकरण को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाया; और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने दशकों तक उसी राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, ऐसा नहीं कि वे अचानक इसके दावेदार बन गये हों।

कुशवाहा सरकार का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए और उनका नेतृत्व किया है, भाजपा और व्यापक जनता परिवार, दोनों के साथ गठबंधन की बातचीत की है, और अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखी है। इसलिए, उनकी अहमियत सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि वह कोइरी नेता हैं या नीतीश के पूर्व सहयोगी रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि वे उस खास जगह को समझते हैं, जिस पर नीतीश काबिज़ थे: सामाजिक रूप से जुड़े हुए लेकिन किसी एक जाति तक सीमित नहीं, भाषा में समाजवादी लेकिन गठबंधन के मामले में व्यावहारिक, और पिछड़े वर्गों के साथ-साथ उस मध्यम वर्ग से भी बात करने में सक्षम, जो सुशासन के वादे पर भरोसा करता था। अगर कोई "अगला नीतीश" हो सकता है, तो कुशवाहा का दावा इस बात पर टिका है कि वह सिर्फ़ कुर्सी के नहीं, बल्कि उस राजनीतिक तौर-तरीक़े के उत्तराधिकारी बन सकते हैं, जिसने नीतीश को इतने लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखा।

लेकिन, कुशवाहा ने विरासत को अलग तरह से परिभाषित करने में सावधानी बरती है। उनके लिए, विरासत का मतलब कुर्सी मिलना, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को राजनीतिक सत्ता का अपने-आप हस्तांतरण नहीं है; बल्कि यह विचारों, मूल्यों और एक राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का पर्याय है। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया का ज़िक्र उनके लिए मायने रखता है। असल में, वे यह तर्क दे रहे हैं कि नीतीश की असली विरासत उस समाजवादी राजनीति में है, जिसे उन्होंने अपनाया, उसमें बदलाव किए और बिहार में चुनावी रूप से प्रासंगिक बनाया, और जो कोई भी उस विरासत का दावा करता है, उसे उन विचारों को आगे ले जाने की क्षमता दिखानी होगी।

यह फ़र्क इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश के जनता दल (यूनाइटेड) के पास उत्तराधिकार के सवाल का बिल्कुल अलग जवाब है। पार्टी के नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को बिहार के भविष्य के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। इस पेशकश को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि वे नीतीश के बेटे हैं और परिवार की राजनीतिक विरासत के सबसे स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं।

लेकिन किसी राजनीतिक नेता का बेटा होना, और उसकी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी होना, ज़रूरी नहीं कि एक ही बात हो। निशांत को अभी उस परीक्षा से गुज़रना बाकी है, जिसका सामना हर राजनीतिक उत्तराधिकारी को कभी न कभी करना ही पड़ता है: अपनी खुद की पहचान, अपना जनाधार और अपनी विश्वसनीयता बनाना।

राजनीति में, खानदान से मिली पहचान एंट्री टिकट तो दिला सकती है, लेकिन यह अपने-आप में लोगों की स्वीकार्यता की गारंटी नहीं दे सकती। समय, राजनीतिक कामकाज और मतदाताओं से जुड़ने की क्षमता ही यह तय करेंगे कि निशांत पारिवारिक विरासत को एक स्वतंत्र राजनीतिक जनादेश में बदल सकते हैं या नहीं।

अब हार्पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस संस्मरण, जिसमें एकांतप्रिय सोनिया गांधी ने युद्ध के बाद के इटली में गुजरे अपने बचपन, नेहरू-गांधी परिवार में शादी, पति राजीव गांधी की हत्या और राजनीति में आने के बारे में लिखा है, ने अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश होने से पहले ही काफी ध्यान खींचा है।

सात राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की आयु सीमा 62 वर्ष हो- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 04 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने सात राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने यह निर्देश दिया। शीर्ष अदालत का कहना है कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को सिस्टम में बनाए रखना जरूरी है।

■ **अदालत ने कहा कि 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वालों की उपयुक्तता के आधार पर रिटायमेंट एज बढ़ेगी। उपयुक्तता की जांच संबंधित हाईकोर्ट करेगा।**

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश को अपने सेवा नियमों में बदलाव करना होगा। महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी सेवानिवृत्ति उम्र 62 साल करनी होगी। इन राज्यों को सेवा नियमों में संशोधन करने के लिए शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह काम जल्द से जल्द किया जाए।

विजय शाह का ऐसा क्या ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ **मध्य प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा जोर लगा रही है, शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की इज़ाजत न देने के लिए।**

नहीं लिया था। सरकार का यह भी कहना है कि मंत्री का मकसद अपनी टिप्पणी से कर्नल कुरैशी या किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करना नहीं था।

राज्य सरकार शाह की माफी पर भी काफी हद तक भरोसा कर रही है। सरकार के प्रस्तावित जवाब के अनुसार, शाह ने तीन बार माफी मांगी और लिखित रूप में खेद भी व्यक्त किया। कैबिनेट का मानना है कि आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला करते समय बार-बार मांगी गई इस माफी पर विचार किया जाना चाहिए।

सरकार ने इस घटना को मानवीय भूल भी बताया है। उसका कहना है कि हालात को देखते हुए, शाह द्वारा बार-बार खेद व्यक्त करने और जानबूझकर ऐसा करने का इरादा न होने को देखते हुए, मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

सरकार के बचाव का एक और अहम हिस्सा यह तर्क है कि शाह के बयान से सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ा। राज्य सरकार यह तर्क दे सकती है कि न तो सांप्रदायिक शांति में कोई वास्तविक व्यवधान आया और न ही मंत्री का ऐसा कोई व्यवधान पैदा करने का इरादा था।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 25 अगस्त को शाह पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी न देने का फैसला किया था। इसके बाद यह सिफारिश राज्यपाल मंगूभाई पटेल को भेजी गई, जिन्होंने कैबिनेट के फैसले को मंज़ूरी दे दी। अब सरकार इन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी।

लेकिन कोर्ट के लिए तैयार किए जा रहे कानूनी तर्कों से परे एक ऐसा राजनीतिक सवाल भी है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सरकार विजय शाह के खिलाफ़ कार्रवाई करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है?

इसका जवाब भाजपा के अंदर, और मध्य प्रदेश की आदिवासी राजनीति में शाह की विशेष राजनीतिक पकड़ में छिपा है।

विजय शाह कोई आम मंत्री नहीं हैं। उन्होंने 1990 से लगातार आठ विधानसभा चुनाव जीते हैं और तीन दशकों से ज़्यादा समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में बने हुए हैं। विधायक के तौर पर अपने आठ कार्यकाल के दौरान, उन्होंने उमा भारती के दौर से लेकर मौजूदा मोहन यादव सरकार तक में काम किया है।

इन सालों में, शाह ने पांच अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने तीन बार आदिवासी कल्याण विभाग और दो बार वन विभाग का नेतृत्व किया है। उन्होंने स्कूल शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति, और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों का भी कार्यभार संभाला है।

सरकार में इतने लंबे समय तक बने रहने के साथ-साथ, ज़मीनी स्तर पर उनका गहरा राजनीतिक प्रभाव भी रहा है।

शाह मकराई राजपरिवार से ताल्लुक रखते हैं और राजगोंड खानदान से हैं। उन्हें मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे प्रमुख आदिवासी चेहरों में से एक माना जाता है, खासकर गोंड वोटरों के बीच।

यह सामाजिक आधार राजनीतिक रूप से बहुत अहम है। मध्य प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जबकि आदिवासी वोटर कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजों को भी प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर, आदिवासी-बहुल सीटों की विधानसभा में बड़ी हिस्सेदारी है।

गोंड समुदाय राज्य के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है और मध्य प्रदेश की आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इस सामाजिक वर्ग में शाह की स्थिति उन्हें उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र से कहीं ज़्यादा राजनीतिक महत्व दिलाती है।

लगभग चार दशकों से हरसूद और आसपास के इलाकों में उनका दबदबा रहा है। लगातार आठ जीत ने उन्हें भाजपा के सबसे मज़बूत क्षेत्रीय नेताओं में से एक बना दिया है।

यही वजह है कि उनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई राजनीतिक रूप से पेचीदा है।

सत्ताधारी पार्टी के लिए, शाह को हटाना, उन पर मुकदमा चलाना या सार्वजनिक रूप से उनसे दूरी बनाना एक ऐसे प्रभावशाली आदिवासी नेता को नाराज़ करने का खतरा है, जिनका नेटवर्क बहुत पुराना है और चुनावी आधार वफ़ादार है।

पहले हुए विवादों के बाद भी, उनका राजनीतिक रूप से बने रहना यह दिखाता है कि पार्टी ने अतीत में उन्हें कितनी सावधानी से संभाला है।

2013 में, झाबुआ में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने पर आलोचना होने के बाद शाह को कैबिनेट से हटा दिया गया था। लेकिन उन्हें हटाने का यह फैसला सिर्फ़ चार महीने तक ही चला और वे फिर से मंत्री बन गए। एक दशक से भी ज़्यादा समय के बाद, एक और विवाद ने उन्हें फिर से राजनीतिक और कानूनी तूफ़ान के केन्द्र में लाकर खड़ा कर दिया है।

लेकिन इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है।

मई 2025 में एक वीडियो सामने आने के बाद शाह की कड़ी आलोचना हुई। इस वीडियो में उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखा गया था, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई थी।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन टिप्पणियों का स्वत: संज्ञान लिया, शाह की कड़ी आलोचना की और पुलिस को उनके खिलाफ दुश्मनी और नफरत फैलाने जैसे आरोपों में एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देश दिया।

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

विवाद के बाद शाह ने खेद व्यक्त किया। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी के तरीके पर उन्हें फटकार लगाई और सवाल उठाया कि क्या उनकी प्रतिक्रिया पर्याप्त थी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422-23, जालौर। फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906-07, फैक्स: 01562-256908